देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवार 17.06.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- राज्य के हर जिले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर्स को प्रोत्साहित करने के लिये उन्हें एक दिन के लिए सांकेतिक रूप से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से राज्य में जल–विद्युत परियोजनाओं के विकास में विशेष सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

- प्रदेश के विकास के लिए दीर्घकालिक नीति निर्माण बनाने के उद्देश्य से देहरादून में ''विकसित उत्तराखंड विजन 2047'' कार्यशाला आयोजित की गई।

- यूसीसी के तहत पंजीकरण कार्य को गति देने के लिए चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

नई पहल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दो नई पहल की घोषणा की है। उनके निर्देश पर राज्य के हर जिले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर्स को एक दिन के लिए सांकेतिक रूप से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को प्रशासनिक अनुभव देना और उन्हें उच्च लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम को जल्द ही जिलों में लागू किया जाएगा, जिसके लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश की प्रमुख नदियों पर 'नदी उत्सव' आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं। यह आयोजन जनसहभागिता के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें नदियों की सफाई, स्वच्छता और संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियां केवल जलस्रोत नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा हैं। 'नदी उत्सव' के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा।

मुलाकात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्य में जल–विद्युत परियोजनाओं के विकास और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में विशेष सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश–हरिद्वार क्षेत्र में बिजली लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने की आवश्यकता जताई। साथ ही कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिये चार हजार करोड़ रुपये के वायबिलिटी गैप फंड की मांग रखी।

दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास के लिये तीन हजार आठ सौ करोड़ रुपये के वायबिलिटी गैप फंड का भी अनुरोध किया। इसके अलावा श्री धामी ने पिटकुल की दो प्रमुख परियोजनाओं की डीपीआर को 100 प्रतिशत अनुदान के साथ मंजूरी देने की मांग की, जिनकी अनुमानित लागत लगभग एक हजार करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मोदीपुरम–मेरठ मार्ग से आगे हरिद्वार तक विस्तारित करने का आग्रह किया, ताकि उत्तराखंड में बेहतर यातायात व्यवस्था और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।

पुनर्वास

देहरादून में बंद होने जा रहे सत्य साईं आश्रम से 14 दिव्यांग अनाथ बालिकाओं को राफेल होम संस्था में स्थानांतरित कर दिया गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। सत्य साईं आश्रम निजी और आर्थिक कारणों से अब इन बालिकाओं को रखने में असमर्थ था।

बालिकाओं को नई संस्था में शिफ्ट करने के लिए जिला प्रशासन ने त्वरित हस्तक्षेप किया। जिलाधिकारी ने स्वयं इस मामले में सख्ती बरतते हुए उच्च अधिकारियों को बालिकाओं के साथ राफेल होम भेजा और उन्हें वहां विधिवत पुनर्वासित कराया।

इससे पहले कुछ संस्थाओं द्वारा दिव्यांग बालिकाओं को प्रवेश न देने की शिकायत सामने आई थी। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए दस बिंदुओं पर जांच के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि यदि मानकों का पालन नहीं किया गया, तो संस्थाओं का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेवा के नाम पर पंजीकरण लेकर धन संग्रहण करने वाली संस्थाओं पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांगों, असहायों और अनाथों के अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तैयारियां–चमोली

चमोली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मतदान स्थलों की स्थिति, रूट मैप और अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को समय से चुनाव संबंधी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और आपदा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। खंड विकास अधिकारियों को मतदान स्थलों का निरीक्षण कर जरूरी सुधार कार्यों की रिपोर्ट देने को कहा गया है।

मतदान कार्मिकों की आवाजाही के लिए रूट मैप और वैकल्पिक मार्गों की सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षित हेलीपेड चिन्हित करने और वन क्षेत्रों में स्थित मतदान स्थलों पर बिजली, पानी और भोजन जैसी सुविधाओं की समय से व्यवस्था करने को कहा गया।

साथ ही नामांकन केंद्र और स्ट्रांग रूम तय कर उनमें सीसीटीवी जैसी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और मतगणना स्थलों की समय से तैयारी पूरी करने के भी निर्देश दिए गए।

कार्यशाला/मंथन

प्रदेश के भविष्य के विकास के लिए दीर्घकालिक नीति निर्माण और उसे लागू करने की रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से देहरादून में ''विकसित उत्तराखंड विजन 2047'' कार्यशाला आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम– यूएनडीपी के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढांचा, अर्थव्यवस्था, रोजगार, स्थानीय स्वशासन, वित्त, सुरक्षा और न्याय जैसे विषयों पर आधारित 218 उभरते संकेतकों की प्राथमिकता तय की गई। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और सेतु आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शत्रुघ्न सिंह ने भाग लिया।

मुख्य सचिव ने कहा कि यह दीर्घकालिक नीति निर्माण, भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक निवेश है और सभी विभागों के लिए इसे प्राथमिकता बनाना होगा। उन्होंने सरकारी अधिकारियों की भूमिका को निर्णायक बताया और कहा कि सेतु आयोग और यूएनडीपी मिलकर इस विजन को मापने योग्य परिणामों और ठोस ढांचे में ढालने का कार्य करेंगे।

सेतु आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि उत्तराखंड को उच्च आय वाले राज्य में बदलने के लिए पूंजी निवेश, तकनीकी नवाचार और समावेशी विकास को अपनाना जरूरी है।

सचिव नियोजन डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी ने कार्यशाला में विकास के विभिन्न बेंचमार्क प्रस्तुत किए।

यूसीसी पंजीकरण गति

चमोली जिले में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत पंजीकरण कार्य को गति देने के लिए जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं। उन्होंने सभी नगर और ग्रामीण क्षेत्र के सब–रजिस्ट्रार और संबंधित अधिकारियों को यूसीसी आवेदनों के शीघ्र निस्तारण करने को कहा।

जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा सीएससी केंद्रों को प्रोत्साहित करने के लिए जनपदवार योजना शुरू की गई है। यह योजना दो चक्रों में लागू की जाएगी। पहला चक्र 10 जून से 10 जुलाई और दूसरा चक्र 11 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगा। प्रत्येक चक्र में 130 से अधिक सफल पंजीकरण करने वाले जिले के पांच सीएससी को पुरस्कृत किया जाएगा।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में हुई विभिन्न हवाई दुर्घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को तीन दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मीडिया में प्रकाशित व प्रसारित हेली दुर्घटनाओं की खबरों का संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश जी० नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

गौरतलब है कि रविवार को गुप्तकाशी से केदारनाथ जा रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सात लोगों की मृत्यु हो गई। इससे पहले, 8 मई 2025 को उत्तरकाशी जिले में एक अन्य हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट सहित छह लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा, तीन अन्य घटनाओं में हेलीकॉप्टरों को आपात लैंडिंग करनी पड़ी थी और अन्य तकनीकी समस्याएं सामने आई थीं।

अदालत ने सरकार से पूछा कि लगातार हो रही इन घटनाओं के पीछे क्या कारण हैं। साथ ही यह भी जानना चाहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन–कौन से कदम उठाए गए हैं और क्या हेली सेवाएं उड़ान चार्ट और मौसम संबंधी नियमों का पालन कर रही हैं।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर...

केदारनाथ–गौरकुंड के बीच हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश जारी किए है। इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला समाचार पत्र का शीर्षक है– हेलिकॉप्टर हादसों पर तीन दिन में स्थिति साफ करें। नवोदय टाइम्स ने लिखा है – हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, सख्त कदम उठाने का आदेश।

उत्तराखंड सरकार मेधावी छात्रों को डीएम व एसपी की भूमिका निभाने का अवसर देंगी। इस खबर पर हिन्दुस्तान ने लिखा है – टॉपर एक दिन के लिए डीएम–एसपी बनेंगे। दैनिक जागरण ने लिखा है – शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में धामी सरकार अभिनव पहल करने जा रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी कार्य मंत्री से मुलाकात की। इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित रूप से होगा योग। इस समाचार पर हिन्दुस्तान समाचार पत्र ने लिखा है – परेड ग्राउंड में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के योग शिविर का शुभारंभ, मंत्री ने भी किया योग।